नागरिक विविध

न्यायमूर्ति एस.बी. कपूर और न्यायमूर्ति एच.आर. सोढ़ी के समक्ष

जे.जे. बावा लाल दास और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

महंत सोहन दास, प्रतिवादी

1968 का उच्चतम न्यायालय आवेदन संख्या 257

18 सितंबर 1968

भारत का संविधान (1950)—अनुच्छेद 133(1)—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5)—एस. 109—गुण-दोष के आधार पर मामले को सुनवाई के लिए भेजने का उच्च न्यायालय का आदेश—ऐसा आदेश—क्या अंतिम निर्णय—उच्चतम न्यायालय में अपील क्या झूठ—"निर्णय"—भारत के संविधान का अर्थ (1950)—अनुच्छेद 133(1)—संहिता सिविल प्रक्रिया (1908 का अधिनियम 5) - एस. 109 - मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए भेजने का उच्च न्यायालय का आदेश - ऐसा आदेश - क्या अंतिम निर्णय - उच्चतम न्यायालय में अपील - क्या झूठ - "निर्णय" - का अर्थ।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए भेजने के उच्च न्यायालय के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1) के अर्थ के तहत अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पार्टियों के अधिकारों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है. एक आदेश जो मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटान नहीं करता है, उसे अंतिम निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता है। किसी आदेश की अंतिमता केवल मुकदमे के संबंध में ही निर्धारित की जानी है। यदि मुकदमा अभी भी जीवित है, जिसमें पार्टियों के अधिकार अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 109 (ए) के तहत ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(पैरा 3)

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि संहिता की धारा 109 के खंड (सी) में शब्द "निर्णय" का अर्थ संहिता में "डिक्री" शब्द के समान है, जिसका अर्थ है मामले में पार्टियों के अधिकारों के अंतिम निर्धारण की घोषणा। मुकदमे में विवाद.

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1) के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि माननीय श्री न्यायमूर्ति एस बी कपूर और माननीय श्री न्यायमूर्ति एच आर सोढ़ी के नियमित द्वितीय अपील संख्या 898 ऑफ़ 1964 में 8 जुलाई 1968 को पारित हुए फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र दिया जाए।

अपीलार्थी की ओर से आत्मा राम, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से वकील एस. एल. पुरी

निर्णय

न्यायमूर्ति सोढ़ी -यह संविधान के अनुच्छेद 133(1) के तहत एक आवेदन है जिसमें प्रार्थना की गई है कि 1964 की नियमित दूसरी अपील संख्या 898, जिसे इस न्यायालय ने 8 जुलाई 1968 को तय किया था, को आगे की अपील के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट। आवेदन के शीर्षक में अनुच्छेद 133 का कोई खंड नहीं दर्शाया गया है जिसके तहत मामला माना जा सके।

(2) ट्रायल कोर्ट ने वादी के मुकदमे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत वर्जित था। पहली अपील की अदालत उस निष्कर्ष से सहमत थी, लेकिन वादी द्वारा इस अदालत में की गई दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी और मामले को योग्यता के आधार पर अन्य मुद्दों के निर्धारण के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज

दिया गया था। यहां उन मुद्दों को दोहराना अनावश्यक है और यह बताना पर्याप्त है कि वादी के मुकदमे का फैसला अभी भी किया जा सकता है यदि वह योग्यता के आधार पर मुद्दों पर सफल होता है।

(3) अपील की अनुमति केवल इस आधार पर मांगी गई है कि इस न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय के फैसले और डिक्री और विवाद में विषय-वस्तु के मूल्य को पहले उदाहरण के न्यायालय के साथ-साथ अब भी बदल दिया है। , रुपये से अधिक है। 20,000. यह मूल्य उस कृषि भूमि की कीमत के आधार पर निकाला गया है जिसका पट्टा प्रतिवादी द्वारा 99 वर्षों के लिए दिया गया बताया गया है। हमने माना है कि यह पट्टा स्थायी अलगाव के समान है। वादी के विद्वान वकील द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने मौखिक रूप से तर्क दिया कि यह पट्टे का मूल्य था जिसे अकेले ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा भी हो, हमें इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं लगता क्योंकि अनुमति को इस संक्षिप्त आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। . वी. एम. अब्दुल रहमान और अन्य बनाम डी. के. कासिम एंड संस और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में यह देखा गया है कि जहां आदेश अंततः मुकदमे के पक्षों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है, इसे अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है या आदेश, भले ही वह मुकदमे की जड़ तक जाता हो और उस पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को शामिल करता हो और अंतिम निर्णय केवल मुकदमे के संबंध में ही किया जाना हो। यदि मुकदमा अभी भी जीवित है, जिसमें पार्टियों के अधिकार अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 109 (ए) के तहत ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। यह सच है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1091 (ए) में, जैसा कि वी. एम. अब्दुल रहमान के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के समय था, 'निर्णय' शब्द प्रकट नहीं हुआ था और इसे बाद में पेश किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 66) द्वारा उस धारा के खंड (सी) में 'निर्णय' शब्द भी

पेश किया गया था, इन सभी संशोधनों का उद्देश्य धारा 109 के प्रावधानों को लाइन में लाना था। अनुच्छेद 133 के साथ। 'निर्णय' शब्द, हालांकि बाद में पेश किया गया, न्यायालयों द्वारा उसी अर्थ में व्याख्या की गई है, जिस अर्थ में नागरिक प्रक्रिया संहिता में 'डिक्री' शब्द का अर्थ है, जिसके द्वारा अधिकारों के अंतिम निर्धारण की घोषणा की जाती है। मुकदमे में विवाद में मामले के पक्षकार। वी. एम. अब्दुल रहमान के मामले में की गई प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियों को मेसर्स जेठानंद एंड संस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा अनुमोदित किया गया था, जहां एक ही परीक्षण को अंतिम रूप देने में लागू किया गया था। निर्णय.

(4) प्रतिवादी के वकील श्री शंभु लाई पुरी ने बॉम्बे स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम दामोदर सवाईलाल, मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किए गए मामलों में व्यक्त किए गए समान विचारों का संदर्भ दिया है। मोहम्मद हसन खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और रतन चंद बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य।

(5) आवेदक के विद्वान वकील श्री आत्मा राम ने हमारा ध्यान सुल्तान सिंह बनाम मुरली धर और अन्य, भारत संघ बनाम कनहया लाई शाम लाल और धनलक्ष्मी विलास काजू कंपनी और अन्य बनाम राष्ट्रपति, जैसे मामलों की ओर आकर्षित किया। काजू इंडस्ट्रीज स्टाफ एसोसिएशन और अन्य। इनमें से कोई भी मामला श्री आत्मा राम की मदद नहीं करता क्योंकि वहां के तथ्य अलग-अलग हैं। सुल्तान सिंह का मामला लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा तय किया गया और जिस पर श्री आत्मा राम ने भरोसा किया, वह उनके खिलाफ जाता है। उस मामले में वादी की अपील पर, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह मानते हुए कि वादी ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अर्थ के भीतर एक हित स्थापित किया था, मामले को शेष मुद्दों पर सुनवाई के लिए भेज दिया। प्रिवी काउंसिल में अपील करने की अनुमति के लिए दायर एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने माना कि उन परिस्थितियों में रिमांड का आदेश अंतिम आदेश के बराबर नहीं था और तदनुसार छुट्टी से इनकार कर दिया गया था। किसी आदेश की अंतिमता के संबंध में मामले का

निर्धारण न केवल मुद्दे की प्रकृति पर निर्भर करता है, बल्कि मुकदमे में उत्पन्न होने वाले अन्य बिंदुओं की तुलना में इसके महत्व पर भी निर्भर करता है। उस मामले में यह देखा गया है कि ऐसा कोई कठोर नियम बनाना असंभव है जो हर मामले में समस्या का समाधान कर सके और जो मुद्दा पार्टियों के अधिकारों का निपटान नहीं करता है, वह उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसे मुकदमे में एक प्रमुख बिंदु के अंतिम निपटान के रूप में माना जा सकता है। मौजूदा मामले में, गुण-दोष के मुद्दे हैं जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मुकदमा या तो डिक्री किया जा सकता है या खारिज किया जा सकता है। कनाहया लाई शाम लाई का मामला (एफ.बी.) भी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को कोई सहायता नहीं दे रहा है।

(6) केरल उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए धनलक्ष्मी विलास काजू कंपनी के मामले में, 'निर्णय' शब्द की वही व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ यह है कि इसे अंततः पार्टियों के बीच विवाद का निपटान करना होगा, जैसा कि एक अंतरिम निर्णय या आदेश के विपरीत है। यह समझ में नहीं आता कि यह निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को कैसे सहायता प्रदान कर सकता है।

(7) उपरोक्त कारणों से, यह माना जाना चाहिए कि मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए भेजने के हमारे फैसले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1) के अर्थ के तहत अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अपील करने की अनुमति के आवेदन का कोई औचित्य नहीं है और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Akshay Arora

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh